

गांवों में कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए 'आधार पे'

■ प्रतीक मिश्र

नई दिल्ली। एसएनबी

कैशलेस अर्थव्यवस्था पर जोर दे रही केन्द्र की मोदी सरकार का फोकस अब गांवों पर है। ग्रामीण क्षेत्र में देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा होने के कारण कैशलेस की सफलता तभी संभव है, जब गांवों तक डिजिटल भुगतान को संभव बनाया जाए।

गांव में रहने वाले किसानों और अशिक्षित लोगों के लिए डिजिटल भुगतान की राह को आसान बनाने के लिए सरकार ने आधार कार्ड आधारित आनलाइन भुगतान सुविधा देने वाले आधार पे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में बैंकों निर्देश दे दिए गए हैं। इस ऐप में न तो किसी कार्ड की जरूरत होगी और न ही किसी पासवर्ड की। इस व्यवस्था में फिंगर प्रिंट की मदद से भुगतान होगा। इस तरह के भुगतान के लिए आधार नंबर, बैंक का नाम और फिंगर

प्रिंट देना होगा। सरकार की कोशिश है कि डिजिटल भुगतान को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। इस तरह के भुगतान के लिए दुकानदार को एक वायोमीट्रिक डिवाइस रखना होगा, जिसमें वह फिंगर प्रिंट ले सकेगा। आधार पे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने बैंकों को निर्देश दे दिए हैं। बैंक की हर शाखा को 40 मर्चेट एनरोल करने के लिये कहा गया है। डिजिटल भुगतान का यह तरीका

अन्य तरीकों से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इसमें गलत इस्तेमाल की गुंजाइश न के बराबर है। ग्राहक और दुकानदार के बैंक खाते आधार कार्ड से जुड़े होने के कारण गलती और दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं है। आधार से जुड़ा होने के चलते यदि कोई फिंगर प्रिंट का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जायेगा। इस ऐप की खासियत यह है कि यदि करते हुये कोई आदमी पाया गया तो बैंक को तुरंत उसकी लोकेशन का पता चल जायेगा।

इस ऐप में न तो किसी कार्ड की जरूरत होगी और न पासवर्ड की, फिंगर प्रिंट से भुगतान होगा